Demand to ease the Credit Card closure process across the country

श्री शंभू शरण पटेल (बिहार): धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे बैंकिंग क्रेडिट कार्ड की सर्विस के संबंध में बोलने का मौका दिया है। महोदय, क्रेडिट कार्ड रखना आज एक स्टेटस सिंबल बन गया है, उसके जहां फायदे हैं, वहीं बहुत नुकसान भी हैं। क्रेडिट कार्ड मिल तो बहुत आसानी से जाता है, लेकिन अगर उसे बंद करना हो, तो बहुत लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बैंक की सभी शाखाओं में क्रेडिट कार्ड संबंधी एक हेल्प डेस्क होनी चाहिए। वहां पर कस्टमर जाए और अगर उसको अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना हो, तो सारे ड्यूज़ क्लियर करके वह उसको बंद करवा सके।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

महोदय, ऐसा हो नहीं पा रहा है। लोगों को क्रेडिट कार्ड तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब बंद करवाना होता है, तो बोला जाता है कि आप ऑनलाइन सम्पर्क कीजिए। ऑनलाइन जाने पर कभी कहता है कि 1 दबाइए, 2 दबाइए, 5 दबाइए, वह दबाता रह जाता है, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होता है, जिसके कारण उसका सिबिल रेटिंग पर इफेक्ट पड़ता है और जब वह किसी दूसरे लोन के लिए एप्लाई करता है, तो उस समय क्रेडिट कार्ड का ड्यूज दिखाई देता है।

मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बैंक की प्रत्येक शाखा में क्रेडिट कार्ड को बंद करने या क्रेडिट कार्ड को देने संबंधी एक हेल्प डेस्क हो, जहां पर कस्टमर जाकर आसानी से अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवा सके या ले सके, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Shambhu Sharan Patel: Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Sulata Deo, (Odisha) and Shrimati Mahua Maji (Jharkhand).

Demand to expedite the notification process for new Land Custom Station between India and Bangladesh

DR. WANWEIROY KHARLUKHI (Meghalaya): Thank you, hon. Deputy Chairman,

Sir, for giving me this opportunity. In one of my Zero Hour mentions, I spoke on the Look South Policy for my State, Meghalaya. The Look East or Act East Policy for Meghalaya is too far a distance, approximately 500 kilometres. South of Meghalaya is Bangladesh, and we have a common boundary of 400 kilometres. To facilitate this Look South Policy, I would request the Government to open up New Land Custom Station between India and Bangladesh. I, strongly, believe that the establishment of New Land Custom Station will significantly benefit both our State and also our country. The introduction of New Land Custom Station will provide substantial employment and will also greatly enhance the economic growth of my people in Meghalaya. This will also facilitate trade and strengthen economic ties between India and Bangladesh. It will contribute positively to the overall economic growth of not only my State but also our country, India. Sir, inspections and reports have already been done by the State of Meghalaya and also by the Customs Department of the Government of India. Hence, through you, Sir, I would like to request the Government to expedite the notification process for the New Land Custom Station in my State. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Dr. Wanweiroy Kharlukhi. The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Wanweiroy Kharlukhi: Shri Madan Rathore (Rajasthan) Shri Samik Bhattacharya (West Bengal), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu).

Demand to accelerate the work related to the construction of tunnel between Bangna and Dhaneta in Himachal Pradesh

डा. सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपने मुझे हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाइवे के कार्य में तेजी लाने व बंगाणा से धनेटा के बीच टनल का निर्माण करने जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को सभा में रखने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण करने का कार्य किसी चुनौती से कम नहीं है। केंद्र सरकार का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जिस प्रकार से फोर लेन और हाइवे का निर्माण कर दूरियों को पाटने का काम कर रहा है, वह सराहनीय है। महोदय, हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत व पोषित दो फोर लेन परवाणु-शिमला व मटौर-शिमला का कार्य प्रगति पर है। इन फोर लेन्स के बनने से जहाँ हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों के लिए भी प्रगति के द्वार खुलेंगे।